जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

चूरू, शनिवार 26 अक्टूबर, 2024

गहलोत सरकार के जाने के ग्यारह महीने बाद अभी भी उस सरकार की बात करने की इतनी उत्कंठा क्यों?

सरकारी तंत्र, सरकारी प्रशासन ''लाइन ऑफ कमाण्ड'' (आदेशों की श्रृंखला) के मार्फत काम करता है। जिला स्तर पर, उदाहरण के लिए पुलिस तंत्र में एस.पी., एडिशनल एस.पी., थानाधिकारी आदि की श्रृंखला होती है। गहलोत ने विधायक को प्रशासन की धुरी बनाकर यह ''लाइन ऑफ कमाण्ड'' तोड़ दिया था और, सभी स्तर के कर्मचारी केवल विधायक की ओर देखने लगे अगले आदेश की प्रतीक्षा में। वरिष्ठता केवल ''अलंकार'' बनकर रह गयी, उसका प्रशासनिक महत्व लगभग खत्म हो गया। इस प्रशासनिक अराजकता से बचने के लिए, पुराने मुख्यमंत्री, कम से कम भैरोंसिंह शेखावत तक, विधायकों की, अफसर की ट्रांसफर-पोस्टिंग की मांग पर दो टूक जवाब देते थे, ''तुम्हारे कहने पर अफसर तो हटा देता हूँ, पर उसकी जगह किसे लगाऊं यह मैं ही निर्णय लूंगा।'' मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार विधायक को ही दे दिया था, इससे प्रशासनिक अराजकता तो फैलनी ही थी। पुराने मुख्यमंत्रियों ने तो प्रशासनिक अराजकता को फैलने से रोकने के लिए कुछ नीतियां-रीतियां बनाईं, लेकिन, गहलोत ने इस अराजकता को सींचने के लिए, पनपाने के लिए, बांध के सब गेट खोल दिये थे। नारा था, प्रशासनिक अराजकता जाए भाड़ में, लेकिन, मेरी सल्तनत सुरक्षित बनी रहे। सरकारी व प्रशासनिक संस्थानों की तोड़-मरोड़ की गूंज ग्यारह महीने बाद भी सुनी जा सकती है। और भ्रष्टाचार के इस पहिए को थमने और पलटने में ना जाने कितने वर्ष लगेंगे।

राजेश शर्मा
प्रधान सम्पादक
राष्ट्रदूत

लगभग साल भर पहले, राष्ट्रदूत ने रॉ के पुराने चीफ, ए.एस. दुलत साहब की नई किताब ''लाइफ इन द शैडोज़'' पर एक ''बुक इवैंट'' (पुस्तक पर गहन चर्चा) आयोजित किया था। दुलत साहब राजस्थान कैडर के आई.पी.एस. अफसर थे, पर अधिकतर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेन्सियों, जैसे आई.बी., रॉ आदि में ''पोस्टेड'' रहे, अत: उनके लिए आयोजित ''इवैंट'' काफी रोचक व ''पॉपुलर'' रहा, विशेषकर, राजस्थान पुलिस उच्चाधिकारियों में। ''वर्ड ऑफ माउथ'' से इवैंट दिल्ली के ''इन्टैलिजैन्स सर्किल'' में भी काफी चर्चित रहा। दिल्ली के जिमखाना क्लब में मेरी जब भी ''इन्टैलिजैन्स ऑफिसरों'' से मुलाकात व चर्चा हुई, तो उनके सभी पुराने साथियों ने ''दुलत साहब'' की किताब को ''हाइ लाइट'' करने को सतही तौर पर काफी सराहा पर मुझे महसूस हुआ, कि, इस सर्किल में दुलत साहब की किताब को लेकर थोड़ी सी ''अनईज़ीनैस'' (बेचैनी सी) भी है।

रॉ के एक रिटायर्ड वरिष्ठतम अधिकारी से, जिसे कालान्तर में थोड़ा मैं गहराई से जानने लगा, एक शाम को अपनी इस ''अनईज़ीनैस'' के अहसास को मैंने शेयर किया और इस अनईज़ीनैस का कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि ''बुक इवैंट'' के बाद मैंने दुलत साहब से बातचीत में पूछा था ''आपने किताब तो बहुत पठनीय व रोचक लिखी, पर कहीं पुस्तक के कारण आप दिक्कत में नहीं आ जाओ, ''ऑफिशियल सीक्रेट्स'' आदि में। दुलत साहब ने एक तरह से ताल ठोकते हुए कहा, मेरे खिलाफ ''ऑफिशियल सीक्रेट्स'' का कोई मामला नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने तो किताब में केवल उन जानकारियों का उल्लेख किया, जो ''पब्लिक डोमेन'' में हैं, (सार्वजनिक तौर पर ''फ्रिली'' उपलब्ध हैं)।

> **जिस बेशर्मी से, निर्दयता से, भ्रष्टाचार पनपाया गया, इतनी बेशर्मी, क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। जायज़-नाजायज़ काम की कुंजी पैसा हो गयी। सरकारी महकमे ''कलैक्शन केन्द्र'' बन गये और हर सक्षम अधिकारी व जनप्रतिनिधि ''कलैक्शन एजेन्ट''।**

''रॉ'' के अधिकारी ने सकुचाते हुए कहा कि दुलत साहब सही कह रहे हैं, जानकारियां ''फ्रीली'' उपलब्ध तो हैं, पर कहीं भी पुस्तक के रूप में नहीं छपीं। अत: ये जानकारियां, ''संदिग्ध'' सी भी हैं, आम जनता के लिए, कुछ कोहरे से में हैं। पर, दुलत साहब ने, जो हमारे पूर्व चीफ थे, इन्हें पुस्तक के रूप में, छापकर, इन जानकारियों को ''ऑथैन्टिकेट'' कर दिया (सत्यापित कर दिया) सारे कोहरे हटा दिए। यह बात थोड़ी सी ''अनईज़ीनैस'' पैदा करती है।

यही स्थिति ''करप्शन'' के बारे में भी है। शायद अनादिकाल से प्रशासन में, सरकारों में, थोड़ा बहुत करप्शन रहा है। पर सरकार व समाज उस पर ''कम बेसी'' नियंत्रण रखता आया है। पर, समाज को प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, भ्रष्टाचार को डाइबीटीज़ की भांति ''परमिसेबल लिमिट्स में'' (अहानिकारक परिधि में) तो सीमित रखा जा सकता है, पर प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया जा सकता।

गहलोत के शासन ने इस ''करप्शन'' को सरकारी मान्यता दी, प्रतिष्ठित किया, व्यवस्थित किया, सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अफसरों को और सरकारी मशीनरी को यह नारा

> **रॉ के पूर्व चीफ दुलत साहब की किताब पर पुलिस के उच्चतम क्षेत्र में ''अनईज़िनैस'' थी, कि उन्होंने वो सब लिख दिया जो लोगों को मालूम तो था पर विश्वसनीयता संदिग्ध थी। किताब ने सब बातों को सत्यापित कर दिया। यही बात ''करप्शन'' को लेकर है। सब जानते थे कि थोड़ा करप्शन तो होता ही है, पर गहलोत ने विधायक को कॉन्स्टिट्युएंसी का मुख्यमंत्री बताकर करप्शन को सरकारी मान्यता दे दी। करप्शन इतना बेधड़क, खुल्लम-खुला होने लगा कि सचिवालय में सरकारी अलमारी में ''रिश्वत'' का सोना व रुपये पकड़े गये, पर जाँच की औपचारिकता ही पूरी हुई।**

देकर, कि स्थानीय विधायक ही अपनी ''कॉन्स्टिट्युएंसी'' (चुनाव क्षेत्र) का मुख्यमंत्री है। उसकी ही चलेगी, और सरकारी मशीनरी उस को समर्थन/सहयोग दे। इस नई व्यवस्था में सरकारी ''इन्स्टीट्यूशन'', (प्रशासन) की परम्पराएं शून्य, प्रभावहीन तो होनी ही थीं और यहीं से खाओ और खाने दो की ही नहीं, बल्कि खाना जायज़ है, की

> **एक उदाहरण जयपुर के नज़दीक कोटपूतली कस्बे का है। वहाँ ''तथाकथित'' सरकारी मापदण्ड के अनुसार रोड चौड़ी करने के लिए 150 घरों व दुकानों में भारी तोड़फोड़ की गई। कइयों के पास खेतड़ी राज्य के पट्टे मौजूद थे, अन्य के पास नगर पालिका द्वारा स्वीकृत नक्शे थे। पर स्थानीय प्रशासन के लिये विधायक क्षेत्र का ''घोषित मुख्यमंत्री'' था। पीड़ित जनता ने न्यायालय से भी आदेश प्राप्त किये, पर न्यायालय के आदेश भी तो अंततोगत्वा प्रशासन ही लागू करता है।**

व्यवस्था बैठाई गई। यह सिस्टम कैसे बना इसकी डीटेल चर्चा आगे करेंगे, किंतु ''करप्शन'' इतना, बेधड़क, खुल्लम-खुल्ला होने लगा, कि सचिवालय में सरकारी अलमारी में ''रिश्वत'' का सोना व रुपये पकड़े गये, पर जांच की औपचारिकता ही पूरी की गई। ''नैट रिज़ल्ट'', यह विश्वास बन गया, कि इसी व्यवस्था का हिस्सा बनें अन्यथा कर्मचारी का भविष्य नहीं है। । प्रशासनिक ''इन्स्टिट्यूशन्स'' को इतना दीमक लगा कि अब शायद कई दशक लगेंगे, करप्शन को ''परमिसेबल लिमिट्स'' में लाने के लिए। यह ''परमानैन्ट देन'' है गहलोत के प्रशासन की। और, यह ''गिफ्ट'' गहलोत बार-बार देना चाहेंगे। क्योंकि उनके मन में कहीं भी कुछ ग्लानि नज़र नहीं आती कि, उन्होंने राज्य में प्रजातंत्र की जड़ें उखाड़ कर फैंक दी हैं। वे मन से विश्वास करते हैं, कि राजा ही तो राज्य है, अत: किसी भी तरह, राजा को बनाये रखना, सुरक्षित रखना ही ''राजधर्म'' है। उनके मन में शायद एक ही अफसोस है, कि पुन: मुख्यमंत्री नहीं बन पाये। वे इसके लिए, रणनीति के क्रियान्वन में कमी को ही हार का कारण मानते हैं। ''करप्शन'' को राज धर्म बनाने के मूल सिद्धांत को कतई बुरा नहीं मानते।

पर, इस विवरण के बाद में भी यह प्रश्न अनुत्तरित सा ही रह गया है, कि अब इस समय उनकी सरकार के जाने के ग्यारह महीने बाद भी निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में बात करने की उत्कण्ठा क्यों है? इस संदर्भ में रामायण का वह प्रसंग स्मरण हो आता है, जब युद्ध के दौरान राम के बाणों की बारिश से घायल होकर रावण मूर्छित हो गया था और उनके सारथी ने उनके रथ को लंका में ले जाने के लिए मोड़ा था, उस समय लक्ष्मण, घायल लंकेश को खत्म करने के लिए तत्पर और तैयार थे। राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है, जिसे जैसे-तैसे भागते हुए घायल तथा मूर्छित अवस्था में मार कर, विजय हासिल करना पर्याप्त है। इसी संदर्भ में राम ने आगे कहा कि यह युद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ा गया है, राज्य पाने के लिए नहीं। रावण अधर्म का प्रतीक है, उसे सबके सामने युद्ध करके और पराजित करके मारना जरुरी

> **सन् 1989 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जोधपुर वासी जिस भी काम के लिए कहते, उनका जवाब होता था, ''यह स्थानीय मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बताओ'' तंग आकर एक आदमी ने हज़ार रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, ''दिल्ली के चांदनी चौक में बाबा छाप ज़र्दे का तम्बाकू मिलता है, अगली बार दिल्ली से आयें तो दो डिब्बे लेते आइयेगा।''**

> **गहलोत के मन में कहीं भी कुछ ग्लानि तक नहीं आती कि उन्होंने राज्य में प्रजातंत्र की जड़ें उखाड़कर फेंक दीं। वे मन से विश्वास करते हैं कि राजा को बनाये रखना ही राजधर्म है। करप्शन को राजधर्म बनाने के मूल सिद्धान्त को वे कतई बुरा नहीं मानते। उनकी सरकार जाने के ग्यारह माह बाद गहलोत के बारे में बात करने की उत्कंठा क्यों है? इस संदर्भ में रामायण का प्रसंग याद आता है। जब मूर्छित रावण को उनका सारथी लंका वापस ले जा रहा था, लक्ष्मण घायल रावण को खत्म करने के लिए तत्पर थे। राम ने उन्हें रोका और कहा कि रावण को सबके सामने युद्ध में पराजित करके मारना जरूरी है, ताकि यह साबित हो जाए कि अधर्म के रास्ते चल कर, फरेब से, छल से चाहे कोई सोने की लंका बना ले, उसका अन्त अशुभ व विध्वंसकारी होता है।**

है। जिससे यह सदा के लिये साबित हो जाये कि अधर्म के रास्ते पर चलकर फरेब से, छल से, चाहे कोई सोने की लंका तो बना ले, पर इसका अन्त अशुभ और विध्वंसकारी ही होता है। राम के कहने का आशय था कि रावण कोई चिन्दी चोर नहीं था, जिसे रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दण्ड देना पर्याप्त है।

किसी भी मायने में गहलोत भी कोई चिन्दी चोर नहीं थे। अत: उन्हें भी चुनाव में हरा देना काफी नहीं है। उनकी हार पर चर्चा करना जरुरी है, क्योंकि, कई मायनों में तो वह ''युग पुरुष'' थे, जिसने सरकार की, प्रशासन की परिभाषा ही बदल दी, अपने कार्यकाल में।

अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी को ''इन्स्टिट्यूशनलाइज़'' कर दिया। यानी सरकारी सिस्टम का ''जायज़'' हिस्सा बना दिया, यह नारा देकर कि विधायक ही अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। ऑन द ग्राउण्ड यह प्रतिलक्षित हुआ, और उसका एक मूल उदाहरण जयपुर के नज़दीक कस्बा-ए-कोटपुतली में देखने को मिला। जहां नैशनल हाई-वे से जुड़ी रोड को ''तथाकथित'' सरकारी मापदण्ड के अनुसार चौड़ा करने और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए लगभग 150 घरों और दुकानों की भारी तोड़-फोड़ की गई। कइयों के पास खेतड़ी राज के पट्टे मौजूद थे, अन्य के पास निगम द्वारा स्वीकृत व पास किये गये नक्शे थे। पर, न्याय के लिए कहाँ गुहार की जाये, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के लिए तो विधायक उस क्षेत्र का ''घोषित मुख्यमंत्री'' था। पीड़ित जनता ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किये पर जनता यह भूल गई कि न्यायालय के आदेश भी अंततोगत्वा प्रशासन ही लागू कराता है।

गहलोत के राज के जाने की वजह उनकी सोच, ''फिलॉसफी'' का सुनियोजित, सटीक क्रियान्वन था। अभाव था या कमी थी तो नैतिक मूल्यों की, स्वस्थ प्रजातंत्रीय फिलॉसफी की, जिसमें शासन की धुरी होती है जनता, न कि राजा, क्योंकि, राजा की बेलगाम महत्वाकांक्षा का खामियाज़ा जनता उठाती है और जनता में आक्रोश फैलता है, और इसी आक्रोश की वजह से गहलोत की हार हुई, उनकी सत्ता गई।

> **गहलोत जन आक्रोश की आंधी के कारण हार गये, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि जनता गहलोत द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली को जाने व पहचाने जिसने हमारे प्रजातंत्र को इतना विकृत बनाया।**

रावण की भांति, केवल गहलोत को हराना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि हार-जीत तो राजनीति का अंग है। गहलोत की हार उस ''फिलॉसफी'' की हार है, जिसमें जनता केवल एक आंकड़ा होती है, और वो ही जीतता है, जो आकड़ों की गणित का सही ''कॉम्बिनेशन'' (संतुलन) बिठा लेता है। गहलोत की इस ''फिलॉसफी'' की अपूर्णता पर चर्चा करना और असार्थकता बताना जरूरी है। यह ही उस उत्कण्ठा के मूल में है, कि गहलोत के सत्ताच्युत होने के ग्यारह महीने बाद भी गहलोत के बारे में बात करने के लिए बेचैनी रहती है, क्योंकि गहलोत शासन प्रणाली की ''फिलॉसफी'' की दुर्बलता, निर्बलता और कुरूपता को समझे और समझाये बिना गहलोत को केवल चुनाव में हरा देना वैसा ही है, जैसे कि घायल मूर्छित रावण को रात के अंधेरे में मार देना, जिसे राम ने वर्जित किया था। उस वध में, राजा की मृत्यु से जनित अवसाद में, रोने-धोने

> **सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में गहलोत की जोधपुर से हार, इतिहास में एक मनोरंजक ''फुट नोट'' बनी। पर ग्यारह महीने पहले गहलोत के नेतृत्व में लड़े गये विधानसभा चुनाव में हुई हार ''फुट नोट'' नहीं, बल्कि देश के प्रजातंत्रीय इतिहास में एक ''काले युग'' के अंत के रूप में उल्लिखित रहेगी।**

> **पुरानी लोकोक्ति थी, ''बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है'', पर गहलोत ने तो हर डाल पर चुन-चुन कर हर स्तर पर ''उल्लू'' बिठा दिया, और साथ में ''फ्रीडम'' दे दी कि ''कमाओ और खाओ'' का सिद्धान्त पूर्णतया स्वीकार्य है।**

में, उस समय की मान्यता व सभ्य समाज के तौर तरीकों से परिभाषित अधर्म, पाप-फरेब आदि की अवांछनीयता दब जाती, उभर कर सामने नहीं आती और राम के वनवास का अघोषित उद्देश्य अपूर्ण रहता।

गहलोत जन आक्रोश की आंधी के कारण हार गये, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, जनता गहलोत द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली को जाने व पहचाने, जिसने हमारे प्रजातंत्र को इतना विकृत बनाया। इतना भयावह व डरावना बनाया।

जिस बेशर्मी से, निर्दयता से, भ्रष्टाचार पनपाया गया, इतनी बेशर्मी, क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। जायज़-नाजायज़ काम की कुंजी पैसा हो गयी। सरकारी महकमे ''कलैक्शन केन्द्र'' बन गये और हर सक्षम अधिकारी व जनप्रतिनिधि ''कलैक्शन एजेन्ट''। पुरानी लोकोक्ति थी, ''बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है'', पर गहलोत ने तो हर डाल पर चुन-चुन कर हर स्तर पर ''उल्लू'' बिठा दिया, और साथ में ''फ्रीडम'' दे दी कि ''कमाओ और खाओ'' का सिद्धान्त पूर्णतया स्वीकार्य है। डर, इस बात का है, कि हर स्तर पर ''उल्लुओं'' को खून मुंह लग गया है, पांच साल में। अब यह ''सिस्टम'' ठीक होने में कई दशक लगेंगे, और जनता ही इसे ठीक कर सकती है, ''बुद्धिमानों'' का भाषण नहीं। मन में उत्कण्ठा गहलोत के बारे में बात करने की इसलिए रहती है कि, जनता पूरी तरह समझ ले कि ''सिस्टम'' को क्या हानि हुई। क्योंकि गहलोत के सोच व कार्य प्रणाली का एक और अनुभव शायद राजस्थान का प्रजातंत्र नहीं झेल पायेगा।

सन् 1989 की बात है, अशोक गहलोत जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उनके आग्रह पर मैं चुनाव कवर करने जोधपुर गया था।

> **गहलोत के तीसरे कार्यकाल में, भ्रष्टाचार की चरम सीमा की पृष्ठभूमि में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक कार्यरत अफसर ने मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए इन हालात के सन्दर्भ में कहा, ''आप सरकार से गलत समय लड़ लिये, यह लड़ने का नहीं कमाने का समय था। कोई सा भी प्रोजेक्ट ले जाइये मुख्यमंत्री के पास, प्रोजेक्ट पर चिन्तन, उससे लाभ की चर्चा नहीं होती, केवल यह पूछा जाता है, तुम्हें कितना लाभ होगा और उसमें ''हमारी'' क्या हिस्सेदारी होगी।''**

आर.टी.डी.सी. के होटल घूमर में ठहरा था। अशोक गहलोत का मैसेज आया, जोधपुर के उद्योगपति घेवर चन्द कानूनगो ने शहर के बड़े-बड़े व्यापारियों को नाश्ते पर बुलाया है, गहलोत भी रहेंगे, आप भी आईये, अच्छी ''न्यूज़'' मिलेगी। नाश्ते के बाद कानूनगो ने 150-200 बड़े आमंत्रित